झारखण्ड सरकार

तृतीय झारखण्ड विधान सभा के पंचम (बजट) सत्र

(28 फरवरी, 2011 से 25 मार्च, 2011)

के अवसर पर

महामहिम राज्यपाल

श्री एम. ओ. एच. फारुक

का

अभिभाषण

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

झारखण्ड, रांची

28 फरवरी, 2011

झारखण्ड विधान सभा के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण,

जोहार!

1. नव वर्ष 2011 के अवसर पर मैं आप सबों के सुख एवं समृद्धि की कामना करता हूँ एवं हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं तृतीय विधान सभा के बजट सत्र के अवसर पर आपको संबोधित करते हुए अपार हर्ष एवं खुशी का अनुभव कर रहा हूँ एवं आप सबों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्य के सर्वांगीण विकास की दिशा में किया गया आप सबों का प्रयास एवं योगदान जन आकांक्षाओं को पूर्ण करने की दिशा में एक सार्थक कदम साबित होगा। यह बजट सत्र मुख्य रूप से विकास के सत्व मुद्दों (Core Issues) एवं क्षेत्रों पर जोर देगा। मेरा विश्वास है कि बजट–बहस में आप सबों की सक्रिय भागीदारी सरकार के लक्ष्यों को पूर्ण करने में सहायक साबित होगी।

2. मैं इस असीम क्षमता वाले राज्य की सेवा करने का अवसर प्राप्त कर गौरवान्वित महसूस करता हूँ। झारखण्ड सिर्फ विस्तृत वनसम्पदा एवं खनिज सम्पदा के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि इसमें यहां के जीवन्त लोगों एवं विभिन्न जनजातीय संस्कृतियों का भी महती योगदान है।

3. राज्य के सर्वांगीण विकास एवं प्रगति की जिम्मेवारी सरकार की है, जिसे जन–जन के ठोस प्रयास एवं गहन जनसहभागिता से प्राप्त किया जा सकता है। यह हमारा सामूहिक लक्ष्य एवं उद्देश्य होना चाहिए। हमें कृषि एवं कृषि जनित क्षेत्रों, सामाजिक क्षेत्रों, आधारभूतसंरचना एवं औद्योगिक क्षेत्रों में समेकित, समान, समावेशी एवं सर्वांगीण विकास तथा प्रगति को सुनिश्चित करना होगा। हम सबों को राज्य में उत्तरदायित्व की भावना, विकास में योगदान करने की तत्परता, सहभागिता एवं सहयोग करने की उदात्त भावना को सृजित करने हेतु प्रयासरत रहना चाहिए। इससे सौहार्दपूर्ण, समतामूलक एवं समग्र समाज का सृजन होगा एवं तभी हम विकास के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप समग्र विकास के सपने को साकार करने हेतु मेरी सरकार जनता को स्वच्छ, न्यायपूर्ण एवं सक्षम शासन उपलब्ध कराने हेतु दृढ़ एवं कृत संकल्प है, ताकि राज्य में विकास प्रक्रियाओं

Honorable Speaker of the Jharkhand Vidhan Sabha and its august members,

Johar

1. My greetings to all of you for a Happy and prosperous 2011!! I feel extremely happy and elated in addressing you at the commencement of this budget session of the 3rd Jharkhand Vidhan Sabha and extend my heartiest best wishes to all of you. I have a firm belief that you will contribute generously to the all round development of the State and show tremendous commitment and honesty to fulfill the aspirations of the people. This budget session will emphasize on the core issues and areas of development. I am confident that all of you will actively participate in the ensuing discussions and support the intent of the government.

2. I feel myself privileged for having been provided with the opportunity of serving this State full of immense potentialities. Jharkhand is known not only for its vast forests and abundant mineral resources but also for its lively people and varied indigenous culture.

3. The overall progress and development of the State is the responsibility of the Government which can be achieved only through a concerted effort and intensive partnership of each and every one of us. It must be treated as our common goal and objective. We must ensure the integrated, equitable and inclusive all-round development and progress particularly in the agriculture and allied sector, social sector, infrastructure building and in the industrial sector. We should strive to inculcate a sense of responsibility and a feeling to contribute to the growth, sense of participation and contribution in each one of the State. This will create a harmonious, egalitarian and unified society. Then only we will be able to make big strides on the path of development. In order to realize the dream of holistic growth at par with the international standards, my Government is determined and pledges to give to its

को गति प्रदान किया जा सके।

4. बुनियादी स्तर पर विद्यमान शासकीय संरचना ही वह आधार है, जिस पर सबल प्रजातंत्र आधारित रहता है। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय आवश्यकताओं एवं इच्छाओं के अनुरूप सिर्फ सहभागी विकास का अवसर ही सृजित नहीं करता है, बल्कि यह शक्ति एवं संसाधन के विकेन्द्रीकरण के लिए संस्थानिक संरचना भी प्रदान करता है। राज्य की शासकीय व्यवस्था में जमीनी स्तर पर स्थानीय प्रजातांत्रिक संरचना का अभाव एक महत्वपूर्ण कमी थी। मेरी सरकार ने विगत तीन दशकों से लम्बित पंचायत चुनाव को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया और यह गौरव एवं संतोष की बात है कि लोगों की उत्साहजनक भागीदारी के साथ चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न करा लिया गया। इस चुनाव में 50,000 जन प्रतिनिधियों, जिसमें 27,000 महिला प्रतिनिधि भी शामिल हैं, निर्वाचित हुई है। यह एक ओर राज्य में महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बल प्रदान करेगा और दूसरी ओर स्थानीय आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को सम्पूर्ण विकास प्रक्रिया का केन्द्र बिन्दु भी बनायेगा। पंचायत शासन व्यवस्था सरकारी तंत्र के निरीक्षण तथा सामाजिक अंकेक्षण के दायरे का महत्वपूर्ण ढंग से सम्वर्द्धन भी सुनिश्चित करेगा। हालांकि हमारे समक्ष इन ग्रामीण एवं शहरी स्वशासी निकायों को विकास एवं शासन का केन्द्र बिन्दु बनाने की वास्तविक चुनौती विद्यमान है, फिर भी मेरी सरकार इन नव चयनित पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों के लिए आवश्यक योग्यता के सम्वर्द्धन हेतु हर संभव प्रयास करेगी ताकि वे अपने पदीय दायित्वों के सफल निर्वह्न के लिए सक्षम बन सकें एवं इन संस्थाओं को पूर्णतः क्रियाशील एवं जीवन्त बना सकें।

5. 34वें राष्ट्रीय खेल अभी सम्पन्न हुआ है। वास्तव में यह एक भव्य आयोजन था। इस विशिष्ट आयोजन के लिए चारों ओर प्रशंसा हो रही है। इस खेल के आयोजन का दायित्व राज्य को 2002 में सौंपा गया था। हमलोगों ने अत्यन्त ही कठिन प्रयास कर इसके आयोजन हेतु अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप आधारभूत संरचना का सृजन किया। कतिपय कारणों से इसका आयोजन कई बार स्थगित हुआ। मेरी सरकार ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया

standards, my Government is determined and pledges to give to its people clean, empathetic and competent governance which would intensify the developmental processes in the State.

4. Democratic Structure of Governance at the grass roots level is the edifice on which the whole democracy rests. Local self governance not only creates the opportunity for participatory development as per the local aspirations but also provides an institutional structure for the decentralization of power and resources. Lack of this grass root local democratic structure was one major shortfall of governance in the State. My Government accorded highest priority to holding the Panchayat Elections in the State which were pending for the last three decades and it is a matter of pride and satisfaction that these elections were conducted in a peaceful manner and people participated with a lot of enthusiasm. These elections have returned over 50,000 representatives including about 27,000 women. This will on one hand, provide huge impetus on the social and economic empowerment of women in the state and on the other shall bring the local needs and aspirations close to realization. It will also significantly enhance the scope of oversight and social audit on government machinery. However, the real challenge before us is to make these local rural and urban self governmental bodies, the centre tool of development and governance. My government will take all measures to sufficiently build the capacity of the newly elected representatives to the Panchayati Raj Institutions so that they adapt to their role perfectly and make these institutions fully functional and vibrant.

5. 34th National Games have just concluded. It was truly a grand show. We are getting accolades from all quarters. These games were awarded to the State in 2002. We worked really hard to create an infrastructure of international standards to host these games. The event got postponed so many times for one or the other reasons.

एवं आप सबों के सहयोग से हमलोगों ने इस खेल का आयोजन अपेक्षाओं से भी बेहतर किया। इस वृहद आयोजन ने झारखण्ड की प्रतिष्ठा में चार चांद लगाया है एवं झारखण्ड को प्रमुखता से राष्ट्रीय मानचित्र पर प्रतिस्थापित किया है। साथ ही इससे हमारा आत्म विश्वास और सबल हुआ है कि हम कोई भी कार्य करने में सक्षम है। झारखण्ड कई खेलों का नर्सरी रहा है एवं इसके गांवों तथा शहरों में खेल प्रतिभायें उपलब्ध है। हाल ही में सम्पन्न राष्ट्रीय खेल ने राज्य में खेल–कूद का एक उत्साहजनक वातावरण तैयार किया है, खेल के लिए सहायक संरचना का सृजन किया है, जो राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत होगा, जो उन्हें अपने–अपने खेल क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्रदान करने में सहायता प्रदान करेगा। मुझे विश्वास है कि यह हमारी युवा ऊर्जा को सृजनात्मक तरीके से आगे बढ़ने में मदद करेगा तथा राज्य के युवाओं के सशक्तिकरण को एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करेगा।

6. अब, इस विश्वस्तरीय खेलकूद की आधारभूत संरचना का रख–रखाव एवं राज्य के खेलकूद के विकास में इसके उपयोग को सुनिश्चित करना राज्य के लिए महत्वपूर्ण है और मेरी सरकार इसके प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस आधारभूत संरचना के रख–रखाव के लिए सरकार ने एक कॉरपस कोष (Corpus Fund) सृजित करने का निर्णय लिया है एवं राज्य में खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित करने पर भी विचार कर रही है, ताकि इस आधारभूत संरचनाओं का सर्वाधिक संभव उपयोग किया जा सके।

7. मेरा विश्वास है कि राज्य का समग्र एवं सर्वांगीण विकास सुशासन से ही संभव है। उत्तरदायी शासन मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार कुशल, पारदर्शी एवं जनोन्मुख प्रशासन प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है।

8. मेरी सरकार भ्रष्टाचार के क्षेत्र में शून्य सहिष्णुता की नीति का अनुसरण करेगी। राज्य में भ्रष्ट कृत्यों को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। सरकार ने भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में अभियान छेड़ दिया है एवं इसे दृढ़ता के साथ चालू रखा जायेगा। सतर्कता तंत्र एवं इसकी आधारभूत संरचनाओं को पर्याप्त एवं प्रभावी ढंग से सुदृढ़ किया गया है तथा विशेष

My Government took it as a challenge and with the support from all corners, hosted the games in a way that not many had even imagined. This mega event has given a real boost to the image of Jharkhand has put Jharkhand prominently on the radar of the whole country. It has also created a sense of confidence in us about our abilities to do even bigger things. Jharkhand is the nursery of many sports and has a huge talent existing in its villages and towns. The just concluded National Games have generated a sporting environment and created a support structure that will provide an impetus for the youth of the State to excel in their fields. I am sure that this will channelize the youth energy in constructive ways and provide real base for empowerment of the youth in the State.

6. It is now, a huge responsibility to maintain this world class sports infrastructure and use it for the development of sports in the State. My government is committed for this. The Government has decided to create a corpus fund for the maintenance of this infrastructure and is also thinking of establishing a Sports University in order to utilize the infrastructure in the best possible way.

7. I am convinced that all-round equitable and holistic development of the State is possible only with good governance in place. Therefore a responsive administration of the highest quality is the topmost priority of my Government. This government is committed to deliver an efficient, transparent and people friendly administration.

8. This Government will have a zero tolerance towards corruption. Corrupt practices will not be tolerated in any form. The government has already started a campaign against corruption which will be continued with firmness in future too. Vigilance machinery and infrastructure have been adequately and effectively strengthened and it has been decided to set up Special Vigilance Courts and Vigilance Cells at divisional level for implementing the anti

सतर्कता न्यायालय एवं प्रमंडल स्तर पर सतर्कता कोषांग के गठन का भी निर्णय लिया गया है, ताकि भ्रष्टाचार उन्मूलन कार्यक्रम का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दोषी व्यक्ति बच न पायें एवं ईमानदार, योग्य एवं कुशल कर्मी अनावश्यक रूप से परेशान न हों।

9. मेरी सरकार का विश्वास है कि गुणवत्तापूर्ण शासन उपलब्ध कराने के लिए सम्पूर्ण प्रशासकीय संरचना को सम्वर्द्धित किया जाय। प्रशासकीय जड़ता के कारकों को ढूँढ निकालने एवं उन्मूलित करने की आवश्यकता है। यह तभी संभव है, जब प्रत्येक स्तर पर कर्मियों का बुद्धिमतापूर्ण एवं उचित उपयोग किया जाए, जटिल नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाए तथा निर्णय प्रक्रिया का आवश्यकतानुसार विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित किया जाए।

10. सरकार ने राज्य में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग तथा आर्थिक एवं मानव संसाधन के समेकित एवं समन्वित विकास संबंधी मुद्दों के निष्पादन हेतु राज्य समन्वय समिति का गठन किया है।

11. मानवाधिकार के सजग प्रहरी के रूप में राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जा चुका है। लोकायुक्त की नियुक्ति कर लोकायुक्त कार्यालय को क्रियाशील कर दिया गया है। राज्य के विकास में युवा शक्ति का उपयोग सुनिश्चित करने एवं युवा शक्ति को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु राज्य युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है।

12. लोगों को उनके घर तक निर्बाध प्रशासकीय सेवा उपलब्ध कराना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार ई–शासन एवं सूचना तकनीक के अधिकतम उपयोग पर विश्वास रखती है। इस दिशा में सार्थक प्रयास करते हुए 2600 प्रज्ञा केन्द्रों को सामान्य सेवा केन्द्रों के रूप में विकसित करते हुए, उसे ऑनलाईन कर दिया गया है। इन सेवा केन्द्रों के माध्यम से जनसामान्य को 15 रु0 के भुगतान पर एक सप्ताह के अंदर बिना प्रखण्ड कार्यालय का चक्कर लगाये ई–नागरिक सेवायें यथा जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र प्राप्त हो रहे हैं। 31 अवर निबंधक कार्यालयों को

corruption program. The government would ensure that the guilty ones do not get any escape and at the same time the honest, deserving and efficient officials do not unnecessarily get harassed.

9. My government however is convinced that for qualitative governance, the whole administrative set-up needs to be energized. The factors responsible for the administrative inertia need to be identified and taken care of. It would be made possible by wise and appropriate utilization of the officials at every level, by simplification of the complex rules and processes and by decentralization of decision making process.

10. The Government has constituted the State Coordination Committee to address all the issues pertaining to proper utilization of the natural resources available in the State and to ensure integrated and coordinated development of the economic and human resources.

11. State Human Rights Commission has been set up as a watchdog of human rights in the State. Office of the Lokayukta has been made functional with the appointment of Lokayukta. It has also been decided to set up State Youth Commission in order to provide a direction to the youth energy and use it in the development of the State.

12. It is a priority of my government to ensure the smooth deliverance of services to the people at the grass roots level. The Government will to a large extent rely on the models of e-governance and information technology. As an effort in this direction 2600 Pragya Kendras established as common service centers have been made online. Common citizens, through these service centers, will get e-nagrik sewa such as birth and death certificates, income certificate and residential certificate at a cost of Rs. 15 per certificate within seven days without going to the block offices. 31 District Sub-Registrar Offices have been computerized enabling the availability

कम्प्यूटरीकृत कर जनसामान्य को निबंधन के ही दिन निबंधन कागजात उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान की गई है। नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता को और अधिक सुगम बनाने के लिए राज्य डाटा केन्द्र की स्थापना एवं राज्य सेवा वितरण द्वार सेवा भी शुरू की गयी है।

13. राज्य में बायोमेट्रिक योजना का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है जिससे सरकारी सुविधाओं का लाभ लक्षित समूहों को सुगमता से प्राप्त होगा। करीब 1.00 लाख लोगों का ग्रामीण क्षेत्र में पंजीकरण भी किया जा चुका है। इसे राज्य के सेवा वितरण पद्धति में सुधार के साधन का महत्वपूर्ण औजार माना जा रहा है। यह विभिन्न सरकारी सुविधाओं तक लोगों के सहज पहुँच बनाने एवं सरकारी विकास कार्यक्रमों यथा मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन, सामाजिक सुरक्षा एवं छात्रवृत्ति योजना का लाभ लोगों तक पहुँचाने में मददगार साबित होगा।

14. मेरी सरकार लोक सेवा की उपलब्धता को अनिवार्य करने की दिशा में कानून बनाने के लिए कटिबद्ध है, ताकि लोगों को अधिकार स्वरूप नागरिक सेवा की गारंटी प्रदान की जा सके एवं सेवा उपलब्ध कराने वाले पदाधिकारियों की जिम्मेवारी एवं दायित्व का निर्धारण किया जा सके।

15. सरकारी विभागों में कर्मियों की अत्यधिक कमी का कुप्रभाव कार्यनिष्पादन पर पड़ रहा है। इसका त्वरित निदान सरकारी तंत्र की कार्यकुशलता के लिए अपरिहार्य है। इस विषय पर मेरी सरकार गंभीर है एवं शीघ्र रिक्तियों का आकलन करते हुए न्यूनतम संभव अवधि में नियुक्ति हेतु कारगर कदम उठाने जा रही है।

16. मेरी सरकार राज्य में गुणवत्तापूर्ण नागरीय सुविधाओं एवं क्षेत्रों के समुचित विकास के लिए कृत संकल्प है। इस संबंध में रांची सहित सभी बड़े शहरों में थ्री–डी मैपिंग सिस्टम का उपयोग किया जायेगा जिससे नागरिक सुविधाओं के लिए आवश्यक सभी आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा सके।

17. झारखण्ड मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित है, जहां 75 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अभी भी कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र पर जीविकोपार्जन के लिए

of registered documents to the people on the same day. In a bid to further expand the coverage of services, State Data Center has been established and State Service Delivery Gateway has also been started.

13. The State has started work on a Biometric System to ensure the pinpointed and targeted delivery of services to the people. About one lakh people have already been enrolled under the system in the rural areas. It would be a handy tool to improve service delivery in the State. It will help people in readily accessing the different services being provided by the State and enjoy the benefits of different developmental programmes particularly related to MNREGA, PDS, Mid Day Meal, Social Security and Stipend Schemes.

14. However, the government, to bring a sea change in the way the public services are being delivered, is preparing to get a law enacted. This will guarantee the delivery of services to the people as a matter of right and will fix accountability on the functionaries who are responsible for the delivery of services. This is the commitment of my government to the people of the State.

15. Acute staff scarcity across the government establishment has been a detrimental factor on the public deliverance. This needs to be addressed immediately to enhance the efficiency of the government. My government is absolutely serious on the issue and shall take appropriate steps to assess the exact number of vacancies and fill them in the shortest possible time.

16. My Government is committed to develop our townships with quality civic amenities for the people. For the purpose we are going to carry out the 3D mapping of all the major towns including Ranchi so that the real time planning can be done to develop the required infrastructure related to civil amenities in these big townships of the State.

निर्भर करती है। राज्य में 38 लाख हेक्टेयर कृषिजन्य भूमि उपलब्ध है, जिसमें यह अधिकतर वर्षा आधारित है। इस वर्ष भी झारखण्ड में सुखाड़नुमा स्थिति है। मानसून वर्षा में 60 प्रतिशत की कमी के कारण फसल आच्छादन, मुख्य रूप से धान 20 प्रतिशत से भी कम रही है। इससे कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। लगातार सुखाड़ के कारण सामान्यजन, खासकर कृषक समुदाय इससे काफी प्रभावित हुआ है। सभी 24 जिलों को सुखाड़नुमा घोषित किया जा चुका है।

18. स्थिति की नाजुकता को भांपते हुए सरकार ने कई योजनाओं के कार्यान्वयन का निदेश दिया है, जिसमें वैकल्पिक फसलीकरण, जलापूर्ति संवर्द्धन योजना, गहरे नलकूप स्थापन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं पंचायत स्तरीय समुचित अनाज भंडारण आदि शामिल है।

19. लगभग 2.00 लाख हेक्टेयर भूमि पर वैकल्पिक फसलीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा किसानों को 10000 क्विंटल दलहन बीज, 8300 क्विंटल तेलहन बीज तथा 4600 क्विंटल आलू का बीज उपलब्ध कराया गया है। उद्‌वह सिंचाई पद्धति सुविधायुक्त 341 पक्का चेक डैम का निर्माण कराया गया है। इसी प्रकार 10572 ड्रीप एवं छिड़काव सिंचाई पद्धति को स्थापित किया गया है। ये सारे प्रयास वर्षा की कमी से उत्पन्न समस्याओं का सामना करने में किसानों के लिए मददगार साबित होंगे।

20. इसी प्रकार सुखाड़नुमा स्थिति से निबटने के साथ–साथ पेयजल समस्याओं के निदान हेतु प्रत्येक पंचायत में 2 उच्च प्रवाही नलकूप स्थापित करने की योजना कार्यान्वित की जा रही है। भूमिगत जलस्तर में सुधार को दृष्टिपथ में रखते हुए विभिन्न जिलों में 1700 वर्षाजल रिचार्जिंग योजना कार्यान्वित की जा रही है।

21. इसी प्रकार सुखाड़नुमा स्थिति के मद्‌देनजर प्रत्येक पंचायत में चिन्हित सार्वजनिक वितरण के दुकानों में 10 क्विंटल अनाज संरक्षित रखा गया है ताकि जीवनरक्षार्थ भुखमरी से ग्रसित व्यक्तियों को त्वरित रूप से आकस्मिक स्थिति में अनाज उपलब्ध कराया जा सके।

17. Jharkhand is a rural economy where more than 75 percent population still depends on agriculture and allied sectors for earning its livelihood. The State, has 38 lakh hectares of arable land. But it is mostly rain fed. Jharkhand has faced severe drought like conditions this year also. The monsoon rains were deficient by about 60 percent from normal. This led to a drop in the crop coverage area, particularly of paddy, to a dismal less than 20 percent. This has adversely affected the agricultural production. This being a successive drought year the common people in general and the farming community in particular have been impacted adversely to a large extent. All the 24 districts of the State were declared to be facing drought like conditions.

18. The Government took a serious note of the situation. Instructions were issued to launch a number of schemes in drought affected districts, including provision for alternate cropping, augmentation of water supply schemes, sinking of deep tube wells, streamlining of public distribution system and storing of food grains in sufficient quantity at every Panchayat level.

19. The government has supported the farmers to take up alternative cropping on 2 lakh hectares area by providing about 10,000 quintals of seeds of pulses, about 8300 quintals of oil seeds and 4600 quintals of potato. 341 pucca check dams have been constructed with lift irrigation system. 10,572 drip and sprinkler systems have been installed. These measures will support the farmers to withstand the effect of shortfall in rains.

20. Likewise in an effort to mitigate the impact to drought on drinking water availability the scheme of digging 2 high yielding deep tube wells in each Panchayat has been taken up. 1700 rainwater recharging schemes have also been taken up in different districts keeping in mind the need to check the depletion of the ground water.

22. सरकार द्वारा सुखाड़नुमा स्थिति से निपटने हेतु निम्नलिखित दिशा–निदेश भी जारी किये गये हैं–

- रोजगार सृजन कार्यक्रम यथा मनरेगा एवं अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन युद्ध स्तर पर किया जाए।
- मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान की जाए।
- पर्याप्त मात्रा में अनाज सार्वजनिक वितरण दुकानों में उपलब्ध रखा जाए।
- अंत्योदय एवं अन्नपूर्णा योजना को शक्ति से कार्यान्वित किया जाए।
- आई0सी0डी0एस0 का कार्यान्वयन निर्बाध गति से किया जाए।
- अवकाश के दिनों में भी मध्याह्न भोजन योजना को चालू रखा जाए।
- वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन का वितरण ससमय सुनिश्चित किया जाए।
- मनुष्य एवं पशुओं हेतु पर्याप्त मात्रा में दवाई उपलब्ध करायी जाए।
- पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध रखा जाए।
- प्रत्येक वन प्रमंडल में मार्ग वृक्षारोपण की योजना चालू की गयी है।

23. मैं आप सबों को यह विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार इस कठिन घड़ी में किसान भाईयों एवं बहनों की सहायता में कोई कमी नहीं बरतेगी तथा हर संभव मदद करेगी।

24. हालांकि यह समझा जाता है कि सरकार किसी भी प्रकार की आकस्मिकता अथवा प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए हर हमेशा तैयार रहती है, फिर भी सरकार द्वारा इस दिशा में पहल करते हुए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार का गठन किया गया है ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति का त्वरित रूप से सामना किया जा सके। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यपालिका समिति का भी गठन किया जा चुका है। आपदा की स्थिति में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से आपातकालीन ऑपरेशन केन्द्र भी स्थापित किये गये हैं। झारखण्ड, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं

21. In view of the prevailing drought like conditions the government has ensured that 10 quintals of rice is stored at a selected PDS shop in each Panchayat to provide food grains to the needy who are in no condition to get it from anywhere else to sustain life.

22. The government also ensured that in these drought conditions –

- Employment generation programmes like NREGP and other schemes pertaining to rural development are implemented at war footing.
- The labourers are paid the minimum wages.
- Adequate quantity of food grains is made available to the PDS shops.
- Antyodaya and Annapurna schemes are implemented to the capacity.
- ICDS is implemented uninterruptedly.
- Mid-Day-Meal is served even on holidays.
- Old age and widow pensions are disbursed on time.
- Medicines for human and live stocks are available in adequate quantities.
- Fodder for live stock is available in adequate quantity, and,
- Large scale avenue plantation is taken up in each forest division.

23. I assure you that the government will leave no stone unturned to support the farmer brothers and sisters in these tough conditions and provide them all possible help.

24. However, there was a felt need that the government should always be in a state of preparedness to face any such exigency or other natural disasters. As an effort in this direction the State has constituted the State Disaster Management Authority and District Disaster Management Authorities to promptly deal with such situations in the future. State Executive Committee has been

उड़ीसा के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने हेतु स्कीपा, रांची में घटना आदेश प्रणाली (Incident Command System) भी स्थापित किया गया है।

25. कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार एक प्रमुख चुनौती है। यहां कृषि वर्षा पर आधारित है। कुल भूमि जोत प्रकार में से 83 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त कृषक की श्रेणी से आते हैं। मानव/भूमि अनुपात के प्रतिकूल होने के कारण यहां की कृषि जीविकापरक (Subsistence Type) है। संसाधन के अभाव के कारण किसानों के लागत का परिमाण (Input Aaplication) न्यूनतम है। यहां एक फसल उत्पादन की प्रधानता, मुख्यरूप से धान की है। 92 प्रतिशत फसल क्षेत्र का आच्छादन खाद्यान्न द्वारा होता है एवं मात्र 3–5 प्रतिशत क्षेत्र में नकदी फसल उपजाये जाते हैं। फसल प्रकार (Cropping Pattern) में विविधता के अभाव के कारण किसानों पर वर्षापात की कमी का कुप्रभाव पड़ता है। कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण प्रवाह नगण्य है एवं विस्तार गतिविधियाँ न्यूनतम हैं। राज्य में एक बारहमासी नदी प्रणाली का अभाव है। यहां सिर्फ मानसून ऋतु में ही वर्षाजल प्राप्त होता है। लहरनुमा स्थलाकृति के कारण वर्षा अपवाह की गति काफी तेज है तथा 72 प्रतिशत वर्षापात अपवाह (runoff) के द्वारा बह जाता है। इन्हीं सब कारकों के समेकन के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थिति के फलस्वरूप कृषि उत्पादकता, उत्पादन, आय, निवेश, धनोपार्जन आदि में कमी होती है, परिणामतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतिहीन हो गयी है। यही कारण है कि राज्य के जी0एस0डी0पी0 में कृषि क्षेत्र का योगदान मात्र 10 प्रतिशत है।

26. हालांकि मेरी सरकार कृषि परिदृश्य को सुधारने के लिए कृतसंकल्प है एवं इस दिशा में एक प्रयास के तहत सरकार द्वारा 75 प्रतिशत अनुदान आधारित उच्च उत्पादकता बीज (high yielding seeds) किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि बीज प्रतिस्थापन अनुपात के 33 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। बीजों की आवश्यकता को पूर्ण करने के मद्देनजर 23 बीज ग्राम एवं 24 बीज प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की गई है। इसके अलावा शुष्क कृषि को बढ़ावा देने हेतु सिंचाई एवं बागवानी युक्त 254 चयनित

constituted with Chief Secretary as its Chairman. Emergency Operations center has been established to do coordination in the event of a disaster. Incident Command System has been established at SKIPA, Ranchi to train the officials of Jharkhand, Bihar, West Bengal and Orissa.

25. Improvement in production and productivity is a major challenge in the agriculture sector. Agriculture is largely rain fed. 83% of the land holdings belong to small and marginal farmers. Agricultural operations are primarily of subsistence type due to the adverse man to land ratio. Application of inputs is minimal because of resource of relative poverty of farmers. There is a predominance of cereal crops particularly paddy in mono culture. About 92 % of Crop area is covered under food grains and hardly 3-5 % area is under cash crops. Lack of diversity in cropping patterns makes the farmers vulnerable to any downward deviation in rainfall. The institutional credit flow to agriculture sector is negligible and extension activities are minimal. The state does not have a perennial river system. It receives water during monsoon season only. Due to undulating topography, the water runoff rate is very high and 72% of the total rain water just runs off. All these factors converge into a vicious cycle of low agricultural productivity, low production, low farm income, low investment, low capital formation and subsequently stagnant rural economy. This clearly shows in, that though about 60% population depends on agriculture for livelihood; its contribution to the GSDP is less than 10%.

26. My government is however committed to correct the agricultural scenario in the state. In an effort in this direction the government is providing high yielding seeds to the farmers at a subsidy of up to 75% and thereby trying hard to enhance the seed replacement ratio to 33%. To meet the heavy requirement of seeds 23 seed villages have been established and 24 seed processing units have been

सूक्ष्म जलछाजन योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें सन्निहित भूमि का क्षेत्रफल 155550 हेक्टेयर है। इसके अतिरिक्त उद्‌वह सिंचाईयुक्त 602 पक्का चेक डैम निर्माण की योजना ली जा रही है, जिसकी सिंचाई क्षमता 17000 हेक्टेयर होगी।

27. बागवानी फसल उच्च उत्पादकता संकेतक है एवं इस क्षेत्र की क्षमता का भरपूर उपयोग किया जा सकता है। फसल विविधता को बढ़ावा देने की दिशा में बागवानी फसल मेरी सरकार का केन्द्र बिन्दु होगा। मेरी सरकार अधिक–से–अधिक भूमि पर फलोत्पादन, सब्जी उत्पादन एवं फूल उत्पादन को बढ़ावा देगी। राज्य में उच्च कोटि के सब्जी का उत्पादन होता है। सरकार किसानों को इच्छित अग्र एवं पश्चगामी संपर्कों से जोड़ेगी ताकि उनका सीधा पहुँच बाजार तक बन सके एवं उनके उत्पादन का अधिकतम लाभ उन्हें प्राप्त हो सके। सरकार द्वारा 6,000 हेक्टेयर बंजर भूमि में काजू की खेती शुरू की गई है जिसे आगामी वर्ष में बढ़ाकर 13,000 हेक्टेयर करने का प्रस्ताव है। सरकार का यह कदम राज्य को राष्ट्र के काजू उत्पादक राज्यों की सूची में शामिल करेगा। सरकार द्वारा फल आधारित बहुस्तरीय फसल पद्धति तकनीक विकसित की गई है, जहां पूंजी/लाभ अनुपात करीब 1:2.5 होगा। नाबार्ड द्वारा बैंकीकृत परियोजना भी विकसित की गयी है। इसके अलावा उच्च घनत्व युक्त फल बगीचा तकनीक भी विकसित किया गया है, जहां पर सामान्य बगीचों की तुलना में फलोत्पादन तिगुणा होगा। किसानों को इस तकनीक को अंगीकृत करने हेतु प्रेरित किया जायेगा ताकि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हो सके। संरक्षित एवं परिशुद्धता कृषि पर भी जोर दिया जायेगा ताकि प्राकृतिक आपदाओं से बचते हुए उच्च गुणवत्ता वाले सब्जी का उत्पादन किया जा सके।

28. बागवानी युक्त फसल विविधता के अंगीकरण से जहां एक ओर उत्पादकता, उत्पादन एवं कृषि आय में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर यह दीर्घकालिक रूप से सुखाड़नुमा स्थिति से निपटने में भी यह मददगार साबित होगा।

29. फसल उत्पादकता में वृद्धि एवं सुखाड़नुमा स्थिति का सामना करने की दिशा

setup. Besides, to bring about improvement in agriculture which is rain fed, irrigation and horticulture based demonstrations are being organised in 254 selected micro watersheds covering an area of 155550 hectares. 602 more pucca check dams with lift irrigation systems are to be constructed to cover an area of 17000 hectares.

27. However horticultural crops have high productivity indicators. There is a lot of potential in this sector which needs to be realized. Crop diversification through horticultural crops will be the focal area of my Government. The Government will provide a lot of thrust for bringing more and more areas under fruits, vegetables and floriculture. The State produces high quality vegetables. The Government would provide the desirable forward and backward linkages so that the farmers can access the market easily and get good price of their produce. The establishment of a terminal market is in the offing and it will be linked with the local markets. The State has put 6,000 hectares of waste land area under cashew nut which is going to be increased to 13,000 hectares in the coming year. This would put the State in the list of leading cashew producers in the country. The State has developed the technology of fruit based multi layer cropping systems where the cost benefit ratio is about 1:2.5. Bankable projects have also been developed by NABARD. Besides, there is technology of high density fruit orchards developed and available in the State where productivity is about three times of the normal orchards. The farmers would be encouraged to adopt these technologies and enhance the productivity and production. The stress would also be laid upon protected and precision farming that would produce high quality vegetables protected from the vagaries of the nature.

28. The crop diversification through horticulture would at one hand increase the productivity and production and subsequently the farm income of the producers, at the other hand would in the long

में सुनिश्चित सिंचाई क्षमता का सृजन एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राज्य की सिंचाई क्षमता 7.40 लाख हेक्टेयर है, जिसमें वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं तथा लघु सिंचाई योजनाओं का योगदान क्रमशः 2.34 लाख हेक्टेयर एवं 5.06 लाख हेक्टेयर है, जो कृषि जन्य भूमि का लगभग 25 प्रतिशत है। अतः राज्य में सुनिश्चित सिंचाई क्षमता सम्वर्द्धन की नितान्त आवश्यकता है।

30. अजय बराज, सुरंगी जलाशय, नकटी जलाशय एवं बटाने जलाशय योजना के मार्च, 2011 तक पूर्ण होने की संभावना है एवं इससे 46,000 हेक्टेयर भूमि की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होगी। इसके अलावा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत् कार्यान्वित की जा रही सिंचाई योजना यथा सोनुआ जलाशय, अपर शंख जलाशय, पंच खेरो जलाशय, कंसजोरे जलाशय तथा गुमानी बराज के जून, 2011 तक पूर्ण होने की संभावना है, जो अतिरिक्त रूप से 43,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता सृजित करेगा। इसके अतिरिक्त लघु सिंचाई कार्यक्रम के तहत 582 योजनायें ली गई हैं, जिसमें 53 चेक डैम, 217 सूक्ष्म उद्वह योजना, 293 कूप एवं 5 वाटर हार्वेस्टिंग योजना शामिल है एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसके पूर्ण होने की संभावना है। इससे अतिरिक्त रूप से 14,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता सृजित होगी।

31. वस्तुतः वित्तीय वर्ष 2011–12 में लघु सिंचाई योजना अन्तर्गत चेक डैम निर्माण सरकार का केन्द्र बिन्दु होगा, क्योकि यह लागत प्रभावी है एवं इसे अल्पावधि में पूर्ण भी किया जा सकता है। ए0ई0डी0पी0 योजना के तहत 176 चेकडैम निर्माण लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई है एवं आशा की जाती है कि आगामी वर्ष में यह पूर्ण हो जायेगा तथा इससे 33,200 हे0 भूमि की सिंचाई क्षमता भी सृजित होगी। परम्परागत सिंचाई साधनों का पुनरूद्धार का कार्य मार्गदर्शक आधार पर प्रारम्भ किया जायेगा क्योंकि यह कृषि कार्य से सीधा संम्बद्ध है।

32. कृषि के अतिरिक्त पशुपालन, गव्य एवं मत्स्य क्षेत्र का योगदान ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण में अविस्मरणीय है। सरकार का लक्ष्य है कि

term help the State to mitigate the effects of drought like conditions on them.

29. Creating assured irrigation potential is another way to increase the productivity of the crops and to mitigate the effects of drought like conditions due to the deficient and erratic rainfall. The State has created about 7.40 lakh hectares of irrigation potential, 2.34 lakh hectares by major and medium irrigation schemes and 5.06 lakh hectares by minor irrigation schemes, till March, 2010 which is about 25% of the cultivable area. Hence there is an urgent need to enhance the assured irrigation potential in the State.

30. Ajay Barrage, Surangi Reservoir, Nakti Reservoir and Batane Reservoir schemes are targeted to be completed by March, 2011. That would create an additional irrigation potential of about 46,000 hectares. Few other irrigation schemes viz. Sonua Reservoir, Upper Shankh Reservoir, Panch Khero Reservoir, Kansjore Reservoir and Gumani Barrage schemes have been taken up under Accelerated Irrigation Benefit Programme and are scheduled to be completed by June, 2011 to create an irrigation potential of about 43,000 hectares. Besides 582 minor irrigation schemes including 53 check dams, 217 micro lift schemes, 293 wells and 5 water harvesting structures have also been taken up to create additional irrigation potential about 14,000 hectares and are scheduled to be completed in the current financial year.

31. In fact, in the year 2011-12 the focus area of irrigation sector would be the construction of series check dams under minor irrigation considering the fact that they are cost effective and can be completed in short time . 176 series check dams in minor irrigation sector have also been taken up under AIBP and are expected to be completed by the next year with an additional irrigation potential of about 33,200 hectares. The restoration of traditional water bodies directly connected with agriculture would also be taken up on pilot

दुधारू पशुओं के नस्ल सुधार, उम्दा गुणवत्तायुक्त दुधारू पशुओं के वितरण, दुग्ध संग्रहण सह शीतलीकरण केन्द्रों के स्थापन, हरा चारा बीज एवं लागत वितरण, पशुचिकित्सा केन्द्रों के सृजन, मत्स्य बीज वितरण एवं संरक्षण आदि कार्याक्रमों को अंगीकृत कर राज्य को दुग्ध, अण्डा, मछली एवं मांस उत्पादन के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाया जाय। मेरी सरकार इन सम्बद्ध क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करेगी क्योंकि इन क्षेत्रों में महिला स्वरोजगार एवं ग्रामीण परिवारों के आयवृद्धि की अपार सम्भावना सन्निहित है। कृषि प्रक्षेत्र के 4 प्रतिशत वृद्धि को प्राप्त करने के लिए इन सहायक क्षेत्रों में 8 से 10 प्रतिशत वृद्धि दर को प्राप्त करने की आवश्यकता है।

33. मेरी सरकार समेकित कृषि योजना को प्रभावशाली तरीके से प्रारम्भ करेगी एवं इसका विस्तारण अनाच्छादित क्षेत्रों में भी करेगी। यह कृषि उत्पादकता में वृद्धि के साथ–साथ ग्रामीण परिवारों की आय में भी वृद्धि करेगा।

34. सरकार का यह प्रयास होगा कि गरीब ग्रामीणजनों के आपसी सहयोग पर आधारित स्वसमर्थित, स्वावलम्बी, सहकारी संस्थाओं का गठन कर ग्रामीण एवं कृषि अर्थव्यवस्था को विकसित किया जाय। सरकार राज्य में सहकारी संस्थानिक संरचना को विकसित करने एवं मजबूत करने के लिए हर सम्भव मद्द करेगी। इस दिशा में 965 पैक्स, 8 जिला केन्द्र सहकारी बैंक तथा 112 प्रशाखाओं को वित्तीय पैकेज देने की प्रक्रिया सरकार द्वारा प्रारम्भ कर दी गयी है। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के तहत 8 जिलों में समेकित सहकारिता विकास परियोजना प्रारम्भ की जा चुकी है। स्वसमर्थित प्राथमिक स्तरीय सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 2,601 महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है तथा दीदी समृद्धि योजना के तहत उनके द्वारा 91.00 लाख रुपये का लाभ भी अर्जित किया गया है। गुमला ग्रामीण स्वसमर्थित मुर्गीपालन सहकारी संस्था द्वारा एन0सी0डी0सी0 सहकारी उत्कृष्टता पुरस्कार जीत कर झारखण्ड सहकारी प्रक्षेत्र का उत्साहवर्द्धन भी किया गया है।

35. किसानों को राष्ट्रीय फसल बीमा योजना, 2009 के तहत 304.11 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति की अनुमान्यता प्रदान की गयी है। बीमा राशि के भुगतान की

basis.

32. Besides Agriculture, Animal Husbandry, Dairy and Fisheries form a formidable allied sector which is important to strengthen the rural economy. It is the aim of the State to make itself self-reliant in the areas of milk, egg, meat and fish production by breed improvement of milch cattle, distribution of improved milch cattle, establishment of milk collection cum chilling centers, distribution of green fodder seeds and inputs, creating veterinary facilities, distribution of fish seed and conserving it in big water reservoirs for fish farming. My Government would appropriately focus on this allied sector as it provides abundant opportunities for self employment amongst women and to supplements the income of rural families. It is also important to have a targeted achievement of 8-10% growth rate in this subsidiary sector to ascertain 4% growth rate in agriculture sector.

33. My Government would implement the Integrated Farming Scheme with greater vigor and extend it to the uncovered areas. It would increase the productivity of agriculture and shall also augment the income of farmers.

34. It is also the endeavour of the government to develop the rural and agricultural economy of the State by enabling the poor masses to be self-supportive, self-reliant and economically strong through cooperative societies based on mutual cooperation. The Government is all for developing and strengthening the cooperative institutional structure in the State. In doing so, the process is on to provide financial package to 965 PACS, 8 District Central Cooperative Banks and their 112 branches. Besides computerization of 8 District Central Cooperative Banks and their 112 branches has also been taken up to strengthen them. Integrated Cooperative Development Project has been taken up under the aegis of National Cooperative Development Corporation

प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जायेगी। सरकार अधिक से अधिक कृषकों को इस बीमा योजना के तहत आच्छादित करने का प्रयास करेगी ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके।

36. मेरी सरकार पूर्ण खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है। इस दिशा में सार्थक प्रयास के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का व्यवस्थीकरण तथा मजबूतीकरण किया जा रहा है। झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम का भी गठन किया जा चुका है एवं इसने अपना खाद्य वितरण का कार्य भी शुरू कर दिया है। खाद्य सुरक्षा में महिला सहभागिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 75,00 महिला स्वयं सहायता समूह को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बद्ध किया गया है। इसके अलावा सरकार 5,000 महिला स्वयं सहायता समूह को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानों की अनुज्ञप्ति निर्गत करने की योजना बना रही है।

37. खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में सम्प्रति 2.00 लाख लाभान्वितों को अन्नपूर्णा योजना के तहत 10 किलोग्राम चावल प्रति परिवार प्रतिमाह मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। अन्त्योदय अन्न योजना एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत क्रमशः 9,17,900 तथा 14,76,100 परिवारों को 1 रुपया प्रतिकिलो की दर से प्रति परिवार प्रति माह क्रमशः 35 किलोग्राम एवं 34 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सभी योजनाये बी0पी0एल0 परिवारों के लिए कर्णांकित हैं। इसके अतिरिक्त 19.62 लाख ए0पी0एल0 परिवारों को अनुदानित दर पर प्रति परिवार प्रतिमाह 15 कि0ग्रा0 खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। अक्टूबर, 2010 से पुर्नसर्वेक्षित 11,44,860 बी0पी0एल0 परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 20 कि0ग्रा0 चावल 1/– रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2011–12 में भी जारी रहेगी।

38. 529 ग्रामीण अनाज बैकों की स्थापना की गई है एवं प्रत्येक बैंक में 40 क्विंटल चावल भण्डारित रखा गया है। जरूरतमंद सम्बद्ध बी0पी0लए0 परिवार इन ग्रामीण अनाज बैंकों से साख स्वरूप चावल प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष

in 8 districts. 2,601 women have benefited through the Self-Supporting Primary Level Cooperative Societies and have earned a profit of Rs. 91 lakhs under the Didi Samridhi Yojana. Gumla Gramin Self-Supporting Poultry Cooperative Society has been awarded cooperative NCDC Cooperative Excellence Award, 2010 giving a boost to the cooperative sector in Jharkhand.

35. The farmers covered under National Crop Insurance Scheme for Kharif, 2009 season have been allowed a compensation of Rs. 304.11 Crores. The process of payment of compensation would start very soon. Government would make all the efforts to bring more and more farmers under the coverage of this insurance scheme so that their interests can be protected.

36. My Government is determined to provide absolute food security in the State. As an effort in this direction the Public Distribution System is being streamlined and strengthened and Jharkhand State Food and Civil Supplies Corporations has been established. It has started distribution of food grains on its own. 7500 self-help groups have been tagged to public distribution system to ensure the participation of women in providing food security. Besides, government plans to issue licenses of PDS shops to additional 5000 woman SHGs.

37. As a measure to provide food security 2 lakh beneficiaries are being provided free of cost 10 Kgs rice per month per beneficiary under Annapurna Scheme. 9,17,900 families under Antyodaya Anna scheme and 14,76,100 families under Mukyamantri Khadyan sahayata scheme are being provided 35 Kg and 34 Kg of rice per family per month respectively at the cost of just Re 1.00 per Kg.These are the schemes for BPL families. In addition to this 19.62 lakh APL families are being provided 15 Kgs of food grains per family per month at subsidized rates. 11,44,860 resurveyed rural BPL families are also being provided 20 Kgs of rice per month

2011–12 में सरकार अतिरिक्त रूप से 417 ग्रामीण अनाज बैंकों को स्थापित करने की योजना तैयार कर रही है।

39. पूर्ण खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के निमित्त जिला एवं प्रखण्ड मुख्यालय स्तर पर भण्डारण क्षमता का सृजन करना अति आवश्यक है ताकि खाद्यान्न प्रवाह को बरकरार रखा जा सके। इस तरह की क्षमता सृजित करने हेतु प्रत्येक जिला में 1000 टन एवं प्रत्येक प्रखण्ड में 250 टन क्षमतायुक्त गोदामों का निर्माण किया जायेगा।

40. मेरी सरकार राज्यवासियों, विशेषकर दूरस्थ एवं दुरूह क्षेत्र वासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। हमारी सरकार ने अन्तिम ग्राम के अन्तिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा के विस्तारण का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है ताकि स्वस्थ झारखण्ड एवं खुशहाल झारखण्ड की परिकल्पना सही साबित हो सके। इस लक्ष्य के अनुरूप राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकों के स्तर को हासिल करने के निमित्त मौलिक आधारभूत संरचनाओं का स्थापन आवश्यक है ताकि वहां से स्वास्थ्य सेवा का वितरण सभी जगहों तक किया जा सके। इसे क्रियान्वित करने हेतु निम्नांकित कदम उठाये गये हैं।

- 319 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है जिनमें से 97 को पूर्ण किया जा चुका है।
- 82 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है, जिनमें से 11 को पूर्ण किया जा चुका है।
- 126 प्रखण्ड स्तरीय 30 शय्यायुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का कार्य प्रारम्भ किया गया है जिनमें से 8 को पूर्ण किया जा चुका है।
- रांची जिला, जहां 500 शय्यायुक्त जिला अस्पताल का निर्माण कार्य जारी है, को छोड़ कर शेष सभी जिलों में 100 शय्यायुक्त अस्पताल निर्माण की योजना सरकार कार्यान्वित कराने जा रही है, जिसे क्रमिक तरीके से 300 शय्यायुक्त अस्पताल में परिवर्तित कर दिया जायेगा। लातेहार, पलामू, देवघर एवं गुमला जिलों में इस प्रकार के 100 शय्या वाले अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण किया

per family at the rate of only 1 Re per Kg since the month of October, 2010. The schemes would continue in 2011-12 also.

38. 529 Village Grain banks have been established and 40 quintals of rice in each of these banks has been stored. Needy tagged BPL families may take rice from these Village Grain Banks on Credit. The Government plans to establish 417 additional Village Grain banks in 2011-12.

39. Creation of storage capacity at the districts and Block head quarters is also essential for maintaining the continuous supplies of food grains for absolute food security. In order to create this capacity, godowns of 1,000 tones capacity at each district head quarter and of 250 tones capacity at each block headquarter would be constructed.

40. My Government is fully determined to provide quality health services to the people of the state particularly to those living in far flung hard to reach areas. We have drawn this goal for us to take the health services to the last person of the last village of the state so that to create Healthy Jharkhand and Happy Jharkhand. As per the goals and objectives set in the Health Policy to catch up with the national health indicators, it is essential to establish the basic infrastructure from where the health services may be delivered. In order to do that –

- Construction of 319 Health Sub Centers has been taken up and 97 of them have already been completed.
- Construction of 82 Primary Health Centers has been taken up and 11 of them have already been completed.
- Construction of 30 bedded Community Health Centers in 126 Blocks has been taken up and 8 of them have already been completed.
- It has been planned to construct 100 bedded District Hospitals in all

जा चुका है।

- विभिन्न राष्ट्रीय उच्चपथ के किनारे चार आघात केन्द्र (Trauma Center) स्थापित करने की सरकार की योजना है ताकि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को ससमय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। इसी प्रकार 6 अतिरिक्त केन्द्रों के निर्माण की योजना भी सरकार बना रही है।
- घाटशिला में बीमार नवजात उपचार केन्द्र स्थापित किया गया है।
- पूर्वी सिंहभूम, रांची, गढ़वा एवं पश्चिमी सिंहभूम में 7 कुपोषण उपचार केन्द्र की स्थापना प्रारम्भ की गई हैं
- 500 शय्यायुक्त अस्पताल के साथ मेडिकल कालेज स्थापित करने की 2 योजना, 1 दुमका एंव 1 सरायकेला–खरसावाँ में प्रारम्भ की जा रही है। सरकार द्वारा 313 करोड़ रुपये की राशि इस कार्य हेतु स्वीकृत भी की जा चुकी है।

41. हालांकि सरकार द्वारा आई0एम0आर0, एम0एम0आर0 एवं नियमित टीकाकरण सूचकों में अपेक्षित सुधार हुआ है, फिर भी इस दिशा में अभी लम्बी दूरी तय करना बाकी है। स्वास्थ्य सेवा सुधार की दिशा में 188 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। गैर सरकारी संस्थाओं एवं विश्वास आधारित संगठनों को रोगी सेवा हेतु 146 एम्बुलेंस उपलब्ध कराया गया है। 40,764 सहिया, जैसा कि मेरे राज्य में आशा को नामित किया गया है, का चयन कर चतुर्थ वर्गीय मॉड्यूल स्तर का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इनके द्वारा ग्रामीणों को परिधीय सहायता एवं स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों तक पहुँचाने का कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

42. मुझे विश्वास है कि ठोस प्रयास के द्वारा हमलोग पर्याप्त आधारभूत संरचना के सृजन एवं लोंगो को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में सफल होंगे।

43. राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण–3 द्वारा यह दर्शाया गया है कि हमारे 59 प्रतिशत बच्चे, जिनकी उम्र 3 वर्ष से कम है, में कुपोषण के लक्षण विद्यमान हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि एन0एफ0एच0एस0–2 की तुलना में इसमें वृद्धि

the districts except in Ranchi where 500 bedded District Hospital is being constructed, and to upgrade them into 300 bedded hospitals in phased manner. Such 100 bedded hospitals have already been established in the districts of Latehar, Palamau, Deoghar and Gumla.

- It has also been planned to establish four Trauma Centers on different National Highways in the state so that the people injured in Road accidents may be accorded proper medical facilities in time. 6 more such centers are also being planned.
- A Sick Newborn Care Unit has been established in Ghatshila.
- Seven Malnutrition Treatment Centers have been started in East Singhbhum, Ranchi, Garhwa and West Singhbhum districts.
- It has been planned to establish 2 Medical Colleges each with 500 bedded hospital in Dumka and Saraikella-Kharsawan. Funds to the tune of Rs. 313 crores have already been sanctioned by the Government for this purpose.

41. The State though has improved its indicators of IMR, MMR, and Routine Immunization but still we have to go a long way. In further improving the health services 188 community health centers have been provided with transport facility. Non Government Organizations and Faith Based Organizations have also been provided 146 ambulances to provide mobility for the patients. 40,764 Sahiyya-as the ASHA are known in our State- have been selected and trained up to the fourth training modules. They are providing peripheral support to the villagers and helping them to access the health facilities.

42. I am sure that with the concerted efforts we would be able to create optimum health infrastructure and provide quality health services to the people of the State.

43. The National Family Health Survey -3 has shown that 59% of

हो रही है। सरकार जीवनचक्र आधारित पोषण प्रणाली प्रारंभ करने पर विचार कर रही है ताकि कुपोषण की समस्या का निदान सफलतापूर्वक किया जा सके।

44. समेकित बाल विकास योजना कार्यक्रम को 6 वर्ष तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। यह योजना राज्य के 38,432 आंगनबाड़ी केन्द्रों से संचालित की जा रही है। इस फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत 6 महीने से 6 वर्ष तक के शिशु, गर्भवती महिला, प्रसूति महिला एवं किशोरियों को पूरक आहार एवं टीकाकरण की सुविधा आवश्यकतानुसार प्रदान की जाती है ताकि उनका सर्वांगीण विकास एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधा सुनिश्चित हो सके। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय–पूर्व शिक्षा प्रदान करना भी सरकार की महती सूची में शामिल है ताकि प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के धारण शक्ति में वृद्धि हो सके। मेरी सरकार का प्राथमिक केन्द्र बिन्दु बाल विकास कार्यक्रम गतिविधियों के धुरी के रूप में आंगनबाड़ी केन्द्रों को विकसित करने एवं सहायता प्रदान करने की भी है।

45. मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों को गर्म एवं ताजा भोजन उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना एक ओर बच्चों को पोषक भोजन उपलब्ध कराती है, तो दूसरी ओर, इससे बच्चों के नामांकन एवं उपस्थिति पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत राज्य के 40,000 विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 40 लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। वर्तमान वर्ष में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की नियमितता को केन्द्र बिन्दु बनाया गया है एवं आगामी वर्ष में भोजन में गुणात्मक सुधार एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों से इसे समृद्ध करने के बिन्दु पर बल दिया जायेगा। राज्य में स्थापित समयबद्ध त्रिस्तरीय सूक्ष्म अनुश्रवण पद्धति के अनुसरण का काफी सकारात्मक प्रभाव मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन पर पड़ा है। खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता पर भी काफी जोर दिया गया है एवं इस निमित्त विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्तोपरान्त उच्च मापदण्डयुक्त क्रियात्मक नयाचार तैयार किया गया है तथा रसोई–माताओं को भी तद्नुसार प्रशिक्षित किया

children under the age 3 do show the symptoms of malnutrition. However the greater concern is that it has shown an increasing trend since NFHS -2. The Government would emphasize a life cycle based agenda for nutrition so that the issue of malnutrition in the children can be addressed successfully.

44. The Integrated Child Development Scheme (ICDS) Programme is on the top of the agenda for overall development of the children up to the age of six years. This programme is implemented from 38432 Aanganwadi centers in the State. Under this flagship Programme, children from the age of 6 months to 6 years, pregnant women, lactating mothers and adolescent girls are provided supplementary nutrition as well as immunization as per their requirement, for overall development and improvement of the health indices. Strengthening of the pre-schooling component for the children in the age group of 3-6 years in Aanganwadi for ensuring higher retention in the primary school level will also be the priority of the Government. The primary focus of my Government shall be to strengthen and support the Aanganwadi Kendras in the State which are the hub of the ICDS activities.

45. Mid Day Meal Scheme provides hot cooked food to the children of class I-VIII. The scheme at one hand provides nutritive food to the children and at the other hand has had a positive impact on enhancing the enrollment and attendance of the children in the school. Mid-day-meal benefits about 40 lakh children in 40,000 odd elementary schools of the State. In the present year the focus has been on the regularity of Mid-day-meal in the schools, the next year the emphasis would be on improving the quality of the food and its enrichment with micronutrients etc. The establishment of a robust real time three tier micro level monitoring system in the state has had a very positive impact on the implementation of MDMS in the State. Emphasis has been given on the food safety and hygiene

गया है। मेरी सरकार की यह प्राथमिकता होगी कि समेकित बाल विकास योजना एवं मध्याह्न भोजन योजना का कार्यान्वयन पूर्ण मनोयोग एवं सावधानी के साथ किया जाए ताकि इसका अधिकतम संभव लाभ राज्य के बच्चों को मिल सके।

46. बाल अधिकार, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन लाने की क्षमता सन्निहित है। अब 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के विद्यालय में नामांकन, उपस्थिति एवं प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराने तथा अनुश्रवण करने का दायित्व सरकार के जिम्मे है। मेरी सरकार इस संवैधानिक दायित्व के निर्वहन करने के लिए कृतसंकल्प है। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सकारात्मक कार्य किये गये हैं। इसी प्रकार अब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार पर बल दिया जायेगा। पर्याप्त संख्या में मध्य विद्यालयों का उत्क्रमण उच्च विद्यालय के रूप में किया जायेगा ताकि न्यूनतम अहर्ता पूर्ण करने की स्थिति में प्रत्येक 5 किलोमीटर की दूरी पर एक उच्च विद्यालय छात्रों को उपलब्ध हो सके। सरकार की योजना यह भी है कि राज्य के 203 पिछड़े प्रखण्डों में प्रखण्डवार एक अंग्रेजी माध्यम का मॉडल विद्यालय शुरू किया जाए एवं केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रकार के 41 विद्यालयों को स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है। राज्य में सुविधाहीन छात्राओं को मुफ्त आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय द्वारा सफल कीर्तिमान स्थापित किया गया है। के0जी0बी0भी0 की सफलता को दृष्टिपथ में रखते हुए सरकार ने +2 स्तर तक इसके उत्क्रमण करने हेतु पहल शुरू कर दी है ताकि छात्राओं को विस्तारित शिक्षा का अवसर प्राप्त हो सके। के0जी0बी0भी0 में छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण, मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। सरकार द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण की दिशा में भी विशेष बल दिया जायेगा क्योंकि शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु यह परम आवश्यक है।

47. सरकार द्वारा छात्राओं के स्कूल छोड़ने की दर को कम करने, उनकी शिक्षा की निरंतरता को कायम रखने एवं शैक्षणिक उत्साहवर्द्धन करने के उद्देश्य से

also and for this, standard operating protocols have been made through expert advice and cook mothers have been trained accordingly. It will be the priority of my Government to implement the ICDS and MDMS with lot of focus and care so that our children get benefited in an appropriate way.

46. The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 has the potential to bring a paradigm shift as far as elementary education is concerned. Now it is the responsibility of the Government to ensure and monitor the enrolment and attendance all the children of 6-14 years of age in the schools and completion of their elementary education. My Government is fully committed towards this constitutional obligation. Elementary Education has got lot many interventions through Sarva Siksha Abhiyaan. Now the similar emphasis would be available to the Secondary Education through Rastriya Madhyamik Siksha Abhiyaan. Sufficient number of middle schools would be upgraded to high schools in order to ensure that there is at least one high school at every 5 Km distance if minimum numbers of children are available. It has also been planned to open English medium model schools in each of the 203 educationally backward blocks of the State. Out of this 41 have already been sanctioned by the Central Government. The Kasturba Gandhi Balika Vidhyalaya has been a successful model for imparting free residential education to the under privileged girl children in the State. Considering the success of KGBVs the government has taken the initiative to upgrade these schools to +2 levels so that these girls get extended education. Establishment of the girl hostels in the KGBVs would be the high priority of my Government. One more area in which the government would lay special emphasis would be the teachers training which is so essential to improve the quality of education.

47. As a major initiative to reduce the dropout rate of the girl students,

वर्ग 8 में पढ़ने वाले सभी वर्गों के छात्राओं को साईकिल मुहैया करायी जा रही है।

48. विद्यालयों में शिक्षकों का अत्याधिक कमी का कुप्रभाव शिक्षण कार्य पर पड़ रहा है। मेरी सरकार शिक्षकों के सभी रिक्त पदों को न्यूनतम संभव समय में, अधिमानतः अब से 4 महीने के अंदर भरने का कार्य करेगी।

49. उच्च शिक्षा के उत्क्रमण को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य में एक केन्द्रीय विश्व विद्यालय, राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय एवं भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची स्थापित किया गया है। मेरी सरकार इन संस्थानो को हर संभव मदद् करेगी ताकि इनका विकास शिक्षण उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में हो सके।

50. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं का आधुनिकीकरण, उत्क्रमण तथा पाठ्यक्रम का अद्यतनीकरण आवश्यक है, ताकि हमारे विद्यार्थियों को प्रतियोगितापूर्ण एवं समकालीन शिक्षा उपलब्ध हो सके। रांची विश्वविद्यालय, बिनोवा भावे विश्वविद्यालय एवं सिद्धो कान्हू विश्वविद्यालय को पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला आदि के निर्माणार्थ अनुदान राशि विमुक्त की जा चुकी है। नवस्थापित नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर एवं कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को परिसर विकास हेतु राशि विमुक्त की जा चुकी है। मेरी सरकार समयबद्ध रूप से शैक्षणिक आधारभूत संरचना के निर्माण को आवश्यक प्राथमिकता प्रदान करेगी।

51. राज्य वासियों को सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल आपूर्ति कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस प्रक्षेत्र में शहरी एवं ग्रामीण नये पम्प जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण, पुराने जलापूर्ति योजनाओं का पुर्नगठन, न्यूनतम अवधि में पम्प जलापूर्ति योजना एवं नलकूप की मरम्मति, जल स्रोतों के गुणात्मक एवं टिकाऊ रख–रखाव पद्धति का विकास एवं भूमिगत जल स्तर की कमी को रोकने के उपाय आदि सरकार की प्राथमिकतायें होंगी।

52. 88 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है जिनमें से 35 को पूर्ण कर लिया गया है एवं 28 योजनाओं के चालू वित्तीय वर्ष के अंत

to facilitate the continuance of their education and to infuse educational enthusiasm all the girl students of class 8 would now be provided with a bicycle. Thus government is now providing bicycles for the girls of all the classes and categories.

48. One more factor which is affecting the school education adversely is the lack of sufficient teachers in the schools. My Government would ensure that all the existing vacancies of the teachers in the schools are filled up in the shortest possible time preferably within a time period of 4 months from now.

49. To upgrade the standards of higher education in the state a Central University, National Law College and Indian Institute of Management, Ranchi have been established in the State. My Government would fully support these institutions to become the Centers of Excellence.

50. It is also of utmost important to modernize and upgrade the infrastructure facilities as well as to update the course curriculum of the Higher Education in the State so as to impart our students a competitive and contemporary education. Grants have been released to Ranchi University, Vinoba Bhave University and Sidho Kanhu Murmu University for the construction of library and laboratories etc. Funds have also been released for the campus development of newly established Nilamber-Pitamber University, Medininagar and Kolhan University, Chaibasa. My Government shall give due priority to educational infrastructure development in a time bound manner.

51. It is a priority of my Government to provide safe and sufficient drinking water to the people of the State. Construction of new piped water supply schemes in urban and rural areas, to reorganize and strengthen the old water supply schemes, to repair the piped water supply and tube wells in minimum time, to develop the system to maintain quality and sustainability of water sources and prevention

तक पूर्ण होने की संभावना है। प्रति पंचायत 5 नलकूप की दर से 3509 नलकूप का स्थापन किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में 2100 नलकूपों के स्थानान्तरण (relocation) के लक्ष्य के विरूद्ध 1786 नलकूपों का स्थानान्तरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं शेष योजनाओं के वित्तीय वर्ष के अंत तक पूर्ण होने की संभावना है। शहरी जलापूर्ति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। मार्च, 2011 तक धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना चालू हो जायेगी।

53. 2,884 नलकूप के लक्ष्य के विरूद्ध 2814 नलकूपों का स्थापन आंगनबाड़ी केन्द्रों में किया जा चुका है। इसी प्रकार वर्तमान वित्तीय वर्ष 10884 नलकूप स्कूल परिसर में लगाने के लक्ष्य के विरूद्ध 10173 नलकूप को स्थापित किया जा चुका है। 15000 विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु शक्ति एवं उद्‌वह पम्प (force and lift pump) का स्थापन प्रक्रियाधीन है।

54. सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कई योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। ये योजनायें इस प्रकार हैं :–

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगता पेंशन योजना, राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बंधुवा मजदूर पुनर्वास योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, आम आदमी बीमा योजना, कर्मचारी राज्य भविष्य निधि कोष योजना आदि। सरकार लक्षित समूह को लाभान्वित करने हेतु इन योजनाओं का प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी।

55. असंगठित क्षेत्र में कार्यरत गरीबी रेखा के नीचे गुजर–बसर कर रहे मजदूरों को स्वास्थ्य बीमा से आच्छादित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्यान्वयन कर रही है। यह योजना राज्य के सभी जिलों में कार्यान्वित की जा रही है जिसमें प्रतिवर्ष 30 रुपये के बीमा शुल्क के आधार पर प्रत्येक परिवार का 30,000 रु0 का बीमा किया जाता है। सम्प्रति 13.5 लाख लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं जिसे बढ़ाकर 20.00 लाख तक पहुँचाया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत सरकार स्ट्रीट भेण्डरों को भी

of depletion of ground water would be the focal areas in this sector.

52. 35 rural pipe water supply schemes out of 88 schemes have been completed and 28 more would be completed by the end of current financial year. 3509 tube wells with the plan of 5 each in every Panchayat have been installed. 1786 tube wells have been relocated against the target of 2100 during 2010-11. The remaining would be completed by the end of the current financial year. Significant progress has been made in the different urban water supply schemes. Dhanbad water supply scheme is likely to be commissioned by the end of March, 2011.

53. Tube wells in 2814 Aanganwadi centers have been installed against the target of 2884. Similarly, 10173 schools have been covered against the target of 10884 in the current financial year. Installation of force and lift pumps is also under process to provide running water in about 15,000 schools and Aanganwadi centers.

54. Numerous programmes have been undertaken under the Social Security schemes. These are, Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme, Indira Gandhi National Widow Pension Scheme, Indira Gandhi National Disability Pension Scheme, State Social Security Pension Scheme, Rehabilitation Programme for the Bonded Labour, National Family Benefit Scheme, Aam Admi Bima Yojna Scheme and Employees State Provident Fund Scheme. The Government shall ensure the efficient implementation of all of these schemes for the benefit of the target groups.

55. The state government is implementing Rashtriya Swastha Bima Yojana to provide health insurance coverage to BPL workers working in the unorganized sector.The scheme is being implemented in all the districts of the State by ensuring each family for Rs.30000 on a contribution of Rs 30 per annum. At present 13.5 lakh people are getting benefited under the scheme which would go up to 20 lakh. It is also planned to include street vendors also in the

शामिल करने जा रही है।

56. मेरी सरकार विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों यथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, आदिम जाति, अन्य पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास करते हुए उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कृतसंकल्प है एवं इसके लिए समावेशी विकास एवं विकास रणनीति पर विशेष बल दिया जा रहा है।

57. मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य में आदिम जाति को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाली योजना को, न केवल चालू रखा जायेगा, अपितु निर्धारित समयसीमा के अंदर इसके लक्ष्य को भी हासिल किया जायेगा।

58. वामपंथी अतिवाद से ग्रसित 9 जिलों यथा लोहरदगा, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, पलामू, लातेहार, गोड्डा, बोकारो एवं लातेहार में आश्रम स्कूल खोला जायेगा।

59. अन्य कल्याणकारी योजनाओं यथा पॉयलट प्रशिक्षण, वायुयान परिचारिका प्रमाण पत्र योजना, छात्रवृत्ति योजना, साईकिल वितरण योजना, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक सहायता योजना, मुफ्त पोशाक योजना, भारत दर्शन योजना, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना आदि को और अधिक प्रभावी एवं उत्साहित ढंग से कार्यान्वित कराया जायेगा।

60. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रभावकारी कार्यान्वयन पर सरकार विशेष बल दे रही है। इसके लिए वृहद पैमाने पर जनजागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है, ताकि उपलब्ध अधिकार का लाभ लक्षित लोगों को मुहैया कराया जा सके। इस संबंध में मीडिया गतिविधियों के माध्यम से वांछित सूचना एवं जानकारी लक्षित जन–जन तक पहुँचाने की जरूरत है। अभी तक 16285 पट्टा अधिकार प्रदान किया गया है। सरकार लंबित सभी दावों के त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक कदम उठा रही है।

purview of this scheme.

56. My Government is pledged to reach to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Primitive Tribes, Other Backward Class and Minority Communities through the various programmes executed for the socio-economic and educational development of these weaker sections of the society by giving thrust on inclusive growth & development strategy with a focus on bringing these sections in the mainstream of developed society.

57. The ongoing programme of Mukhyamantri Khadya Suraksha Yojana which provides 35 kilogram of free food grains to the families of the Primitive Tribes shall not only be continued but also the targets shall be achieved in the given time frame.

58. Ashram Schools would be established in nine left wing extremism affected districts viz Lohardaga, East and West Singbhum, Chatra, Palamau, Latehar, Godda, Bokaro and Latehar.

59. Other welfare schemes like Pilot Training, Air Hostess Certificate Scheme, Scholarship Scheme, Bicycle Distribution Scheme, Scheme for Assistance in case of Atrocities against SC, Free Uniform Scheme, Bharat Darshan Scheme and Examination Fee Reimbursement would also be implemented with greater focus and zeal.

60. One of the prime focuses of this Government would be the effective implementation of the Forest Rights Act, 2006. This needs massive awareness generation amongst the masses to access the facilities which can be possible only through rigorous mass campaign in terms of Information, Education and Communication through various media activities. Till now 16285 lease rights have been awarded. The Government would see that all the claims are disposed off expeditiously.

61. Under the minority welfare scheme 5281 people were sent on Haz

61. 2009–10 में अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत 5281 लोगों को हज यात्रा पर भेजा गया है। सरकार ने कब्रिस्तान की घेराबन्दी, अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण, व्यवसायिक शिक्षा, हज भवन निर्माण, बहुप्रक्षेत्रीय अल्पसंख्यक विकास कार्यक्रम, छात्रवृत्ति योजना आदि के त्वरित कार्यान्वयन की व्यवस्था की है।

62. विकास परियोजनाओं के लिए भूमि की अनुपलब्धता राज्य में एक विचारणीय बिन्दु रहा है। भूमि अधिग्रहण सदैव एक ऐसा मुद्दा रहा है, जिसने या तो परियोजना को विलम्बित किया है अथवा इसे शुरू ही नहीं होने दिया है। इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल के तहत राज्य सरकार ने झारखण्ड राज्य स्वैच्छिक भूमि अधिग्रहण नियमावली सूत्रित कर लिया है, जो भूमि अधिग्रहण के बदले भू–स्वामी को उम्दा क्षतिपूर्ति भुगतान सुनिश्चित करेगा। भू–स्वामी द्वारा भूमि अधिग्रहण की स्वैच्छिक सहमति देने के उपरान्त उसे पूर्व में मिलने वाले क्षतिपूर्ति राशि की तुलना में दुगुनी राशि प्राप्त होगी। इस सुधार से एक ओर परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु शांतिपूर्ण भूमि अधिग्रहण का मार्ग प्रशस्त होगा, तो दूसरी ओर भू–स्वामियों को शानदार क्षतिपूर्ति प्राप्ति की संभावना भी सुनिश्चित होगी।

63. झारखण्ड सरकार द्वारा अब शहरी भूमि (अधिसीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम 1999 को अंगीकृत किया गया है। इसी के साथ शहरी भूमि (अधिसीमा एवं विनियमन) अधिनियम 1976 स्वतः निरसित हो गयी है। इससे शहरी अधिसीमा में सन्निहित भूमि अब आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपलब्ध हो सकेगी एवं यह जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के तहत राज्य को केन्द्र से अतिरिक्त राशि प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

64. राज्य में औद्योगिक विकास की असीम क्षमता है। झारखण्ड में औद्योगिक विकास को सुगम बनाने हेतु झारखण्ड औद्योगिक नीति 2001 को 31 मार्च, 2011 तक के लिए प्रभावी बना दिया गया है तथा अनुदान हेतु प्राप्त सभी आवेदनों का निस्तारण का कर दिया गया है। विभिन्न अनुदान यथा पूंजी निवेश अनुदान, ब्याज अनुदान, स्टांप शुल्क अनुदान तथा निबंधन अनुदान के

Pilgrimage in 2009 and 2010.Government has made the provision for boundary wall of kabristan, minority hostels, furnishing of hostels, vocational training and construction of Haz House, multi-sectoral development of the minorities and for scholarship schemes.

62. Non-availability of land for the developmental projects has been an area of concern in the State. Land acquisition has always been an issue that either delayed the projects or made them a non-starter. As a major policy initiative in this regard, the State Government has now formulated the Jharkhand State Voluntary Land Acquisition Rules to ensure better compensation to the land owners in lieu of acquisition of their land. The voluntary consent to land acquisition would now get the land owners almost double the compensation to what they might have otherwise received. This reform initiative is likely to ensure hassle free land availability for the projects and ensure to the land owners a fair price for their land.

63. The State of Jharkhand has now adopted the Urban Land (Ceiling and Regulation) Repeal Act, 1999. With this the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 stands repealed. This would make the land involved in urban ceiling, available for increased housing needs. This would also enable the State to access additional resources from the Central Government under JNNURM.

64. There is a great potential for industrial development in the State. In a bid to facilitate the growth of industries the Jharkhand Industrial Policy, 2001 has been made effective till 31st March, 2011 and all the applications received for the grant of subsidy under this Industrial Policy have been disposed off. An amount of about 17 crore rupees has been sanctioned under various subsidies such as capital investment subsidy, interest subsidy, stamp duty subsidy and registration subsidy. Moreover, an amount of 12 crores has

तहत 17 करोड़ रु0 की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त 12 करोड़ रु0 का वितरण विभिन्न उद्योगों को पूर्व में ही किया जा चुका है।

65. झारखण्ड राज्य में तसर सिल्क उत्पादन क्षमता का समुचित उपयोग करने हेतु गंभीर प्रयास किया जा रहा है। परिणामतः वित्तीय वर्ष 2009–10 में राज्य का तसर उत्पादन 406 मिट्रिक टन रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में तसर सिल्क उत्पादन 700 मिट्रिक टन के ऊँचाई को छू सकता है। आगामी वर्षों में इसके अग्रेत्तर विस्तारण की योजना है एवं मैं आशा करता हूँ कि अगले 5 वर्षों में राज्य का तसर उत्पादन दर 2000 मिट्रिक टन प्रतिवर्ष हो जायेगा। राज्य के 5000 कोया पालक (Cocoon Rearer) महिलाओं को स्वास्थ्य बीमा सुविधा से आच्छादित किया गया है। झारखण्ड देश में इस तरह की सुविधा मुहैया कराने वाला प्रथम राज्य है।

66. आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्र में मुख्य रूप से सड़क एवं विद्युत प्रक्षेत्र की ओर सरकार का विशेष ध्यान है। राज्य सरकार औद्योगिक एवं कृषि प्रक्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश को भी बढ़ावा दे रही है।

67. राज्य में 1900 किलोमीटर राज्य उच्च पथ एवं 4800 किलोमीटर प्रमुख जिला सड़क है। इन सड़कों का उत्कृष्ट रख रखाव राज्य की गतिशीलता को बनाये रखने के लिए अतिआवश्यक है। राज्य सृजन के बाद वर्ष 2009–10 तक सरकार द्वारा 4300 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण एवं 72 पुल निर्माण का कार्य कार्यान्वित कराया गया है, जिसमें कुल 1800 करोड़ का निवेश सन्निहित है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 290 किलोमीटर सड़क एवं 12 पुल निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अभी भी काफी कुछ करना बाकी है। हाल में सरकार द्वारा राज्य उच्चपथ प्राधिकार का गठन किया गया है, जो सड़कों के उचित विकास, रखरखाव एवं प्रबंधन का कार्य संपादित करेगा। इसी प्रकार सरकार द्वारा झारखण्ड त्वरित सड़क निर्माण कम्पनी लिमिटेड, जो संयुक्त उद्यम के रूप में सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति पर कार्य करेगी, को प्राथमिक रूप से निर्माण, संचालन एवं हस्तांतरण (बी0ओ0टी0) के आधार पर 1500 किलोमीटर सड़क के उत्क्रमण के लिए

already been disbursed to various industries on these counts.

65. Serious efforts have been made to realize the great potential of tassar Silk production in the State. As a result the State produced 406 metric tonnes of tassar silk in 2009-10. It may touch the mark of 700 metric tonnes in the current year. This would be further expanded in the coming years and in five years we expect to produce 2000 metric tons of tassar silk yearly in the state. Facility of health insurance is being extended to about 50000 women cocoon rearers. Jharkhand is the first State in the country to provide such facility on a large scale.

66. Infrastructure development particularly in the road and power sectors is engaging the attention of the government. The State is making efforts to attract direct investment in the industrial as well as farm sectors.

67. The State has about 1900 kilometers of state highways and about 4800 kilometers of major district roads. It is very important to keep all these roads in excellent condition so as to provide smooth mobility throughout the state. After the creation of the State the widening and strengthening of about 4300 kilometers of roads along with the construction of 72 bridges has been taken up till 2009-10 involving an investment of about 1800 crores. In the current financial year work on 290 kilometers of road and 12 bridges has been completed. Still a lot needs to be done. The Government has recently constituted State Highway Authority of Jharkhand for ensuring the proper development, maintenance and management of the State Highways and such other roads. Government has also constituted Jharkhand Accelerated Road Construction Company Ltd., a joint venture with IL&FS as a Special Purpose Vehicle in the Public Private Partnership mode, primarily to upgrade about 1500 kilometers of state roads on Built, Operate and Transfer basis. Government is also considering the

गठित किया गया है। सरकार गुणवत्ता नियंत्रण निदेशालय की स्थापना पर विचार कर रही है ताकि राज्य पथों के निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

68. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लक्ष्य गैर अनुसूचित क्षेत्र में 500 से अधिक जनसंख्या वाले बसावटों तथा V अनुसूचित क्षेत्र में 250 से अधिक जनसंख्या वाले बसावटों को जोड़ने की है। प्रथम चरण में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1000 या उससे अधिक जनसंख्या वाले बसावटों एवं V अनुसूचित क्षेत्र में 500 या उससे अधिक जनसंख्या वाले बसावटों के पथ संयोजन हेतु योजना ली जा रही है। विशेष अभियान के तहत वाम अतिवाद से ग्रसित 11 जिलों के 250 या इससे अधिक जनसंख्या वाले बसावटों को सड़क से संयोजित करने हेतु योजना ली जा रही है। अभी तक इस तरह के 3060 बसावटों को 5788 किलोमीटर पथ निर्माण कर जोड़ा जा चुका है जिसमें कुल निर्मित पथों की संख्या 1030 है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1225 किलोमीटर पथ निर्माण करते हुए 762 बसावटों को जोड़ा जा चुका है। इसी प्रकार 1555 पथों, जिसकी कुल लम्बाई 5655 किलोमीटर है, का कार्य प्रगति पर है। यह 4304 बसावटों को संपर्क पथ उपलब्ध करायेगा। इस योजनान्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त 8500 किलोमीटर ग्रामीण पथ निर्माण करने हेतु भारत सरकार से संसाधन प्राप्त करने के लिए सार्थक प्रयास किया जा रहा है।

69. राज्य के ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत एवं सुधार करने के लिए सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना प्रमुख योजना है। इसके तहत 15563 ग्रामों में आधारभूत संरचना स्थापित की गयी है एवं 8296 ग्रामों का विद्युतीकरण पूर्ण किया जा चुका है। 16,60,928 बी0पी0एल0 परिवारों के लक्ष्य के विरूद्ध 9,87,311 परिवारों को विद्युत संयोजन दिया जा चुका है। इनमें से 4,62,232 परिवार विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं। टी0भी0एन0एल0 द्वारा 420 मेगावाट उपरी क्षमता के विरूद्ध 390 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। पतरातू ताप विद्युत संयंत्र का जीर्णोद्धार किया जा रहा है ताकि इसके विद्युत उत्पादन क्षमता में अपेक्षित वृद्धि लायी जा सके।

establishment of a Directorate of Quality Control to lay greater emphasis on the quality of the roads.

68. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna targets to connect all habitations having a population of more than 500 in non scheduled areas and that of more than 250 in schedule V areas. In the first stage of implementation, all the habitations having a population of 1000 and above and those having population of 500 or more in schedule V areas are being taken up. In the identified 11 Left Wing affected districts, all habitations having a population of 250 or more are being covered as a special case. Till now 3060 hitherto unconnected habitations have been provided connectivity by covering 5788 kilometers on 1030 such roads. In the current year itself 1225 kilometers of road has been completed providing connectivity to 762 habitations. Work is in progress on 5655 kilometers of 1555 roads. This would provide connectivity to 4304 habitations. Efforts are being made to get resource support from Government of India for taking up additional 8500 kilometers of rural roads under this scheme in the next financial year.

69. Similarly serious efforts are being made to strengthen and improve the power sector in the State. Rajiv Gandhi Rural Electrification Scheme is an umbrella scheme for the electrification of the rural areas. Under this, the basic infrastructure has been established in 15563 villages and 8296 villages have already been energized. Against the target of 1660928 BPL families 987311 families have been provided power connections. Out of this 462232 families are accessing the electric supply. TVNL is producing about 390 MW power on an average against the built up capacity of 420 MW. Patratu Thermal Power Plant is being refurbished to improve the power production from it.

70. Additional schemes have been taken up to create additional grid power of 1600 MVA in the next two and half years. Likewise efforts

70. आगामी दो ढाई वर्षों में अतिरिक्त रूप से 1600 एम0भी0ए0 ग्रिड शक्ति सृजन हेतु अतिरिक्त योजनायें कार्यान्वित की जा रही है। इसी प्रकार संचरण क्षमता में वृद्धि हेतु आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। इन सब प्रयासों के फलस्वरूप यह आशा की जाती है कि वर्तमान संचरण क्षमता 2760 एम0भी0ए0 में 500 एम0भी0ए0 की वृद्धि होगी। पुर्नगठित त्वरित शक्ति विकास तथा सुधार कार्यक्रम के तहत् भी आवश्यक पहल शुरू की गई है ताकि गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो सके एवं चिन्हित शहरों में, जिनकी जनसंख्या 30,000 है, में व्यापारिक ह्रास को कम किया जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र में 4000 एम0भी0ए0 अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन क्षमता सृजित करने के लिए भी सरकार कटिबद्ध है।

71. मैं यह भी आशा करता हूँ कि आधारभूत संरचना प्रक्षेत्र में किये गये विभिन्न पहलों का आशा के अनुरूप नतीजा सामने आयेगा एवं राज्य के औद्योगिक एवं कृषि प्रक्षेत्र के विकास के लिए यह अनुकूल वातावरण तैयार करेगा।

72. मैंने, मेरी सरकार की जनहित संबंधित प्राथमिकताओं एवं वादाओं का विस्तृत अध्ययन किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार उत्तरदायी प्रशासन प्रदान करेगी एवं इसका लाभ जन–जन को मिलेगा।

73. इस राज्य का सृजन अनेक आशाओं एवं आकांक्षाओं के साथ किया गया था। अब यह राज्य एक दशक पुराना हो चुका है। यह भी सही है कि इस राज्य को राजनीतिक अस्थिरता एवं खण्डित जनादेश की भारी कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन खण्डित जनादेश विधायिका पर महती सामुदायिक उत्तरदायित्व सौंपता है। अब यह विधायिका का दायित्व है कि वह राज्य के विकास के लिए हर संभव प्रयास करे ताकि राज्य की जनता के सपनों एवं आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके, जिसे जन–जन ने राज्य सृजन के वक्त देखा था।

74. प्रजातंत्र उदार भावना, पारस्परिक समझ, समन्वय एवं सहयोग पर कार्य करती है। यह हम सभी का दायित्व है कि सबों के उत्थान के लिए हम कार्य करें। यह हरेक के लिए समान आचार संहिता प्रदान करती है। व्यक्ति अथवा दल के हित के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। प्रजातंत्र में हम सबों को जनता

are being made to strengthen the transmission capacity. With these it is expected to enhance the transmission capacity by additional 500MVA from the present level of 2760 MVA. Proper action has been initiated under the Restructured Accelerated Power Development and Reforms Programme to ensure quality power supply to the consumers and also to reduce the commercial losses in the 30 identified towns having the population more than 30000. Government is committed to create capacity for generating additional 4000MVA power in the public sector.

71. I do hope the initiatives being taken in the infrastructure sector would produce the expected outcomes and help in creating a favorable environment in the industrial and farm sectors.

72. I have enumerated in detail the priorities and commitments of my Government to the people of the State. I assure you that my Government would leave no stone unturned to provide a responsible administration and take the benefits of all-round and equitable development to one and all.

73. This State was created with lot of hopes and aspirations. Our State is now about a decade old. This however is also true that the State has paid a heavy price for the political instability and the fractured mandates. But, the fractured mandate puts larger collective responsibility on the legislature. This is the responsibility on the legislature that it makes all the efforts to develop the State as per the dreams and aspirations of the people with which this State has been created.

74. Democracy works on liberal spirit, mutual understanding, coordination and cooperation. It is for all, to work for the upliftment of all. It provides the same code of conduct for everybody. There is no specific place for personal or party interest. We have to be very aware and alert about our role and responsibility towards the people in the democratic system.

के प्रति अपनी भूमिका एवं जिम्मेवारी के प्रति सावधान एवं सजग रहना होगा।

75. मैं आशा करता हूँ कि हम सब मिलकर जनाकांक्षाओं को पूर्ण करने में सफल होंगे एवं आप सबों के ठोस प्रयास से इस राज्य के जन–जन का सपना साकार हो सकेगा।

मैं अपने अभिभाषण को इन्हीं आशाओं एवं उम्मीदों के साथ समाप्त करता हूँ।

जय झारखण्ड ! जय हिन्द !

75. I hope we together will come true to the expectations of the people and with your concerted efforts the people of the state would very soon be able to live their dreams.

I conclude my address with this high hope and expectations from you.

Jai Jharkhand !! Jai Hind !!